



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 3, 2017 (PHALGUNA 12, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 मार्च, 2017

संख्या 2/23/2016-1 पेंशन.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग-II नियम, 2017, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

(2) ये नियम सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को लागू होंगे, जो 01.01.2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं/मृत्यु हो गई है हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अधीन अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो गए हैं तथा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को लागू है तथा जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन हरियाणा राज्य की समेकित निधि से विकलनीय है।

2. ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

इन नियमों का अलागूकरण।

- (i) ऐसे व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग को जिनकी सेवाएं हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के उपबन्धों अथवा किन्हीं सेवा नियमों, जो पेंशनरों के मामले में लागू हैं, के उपबन्धों द्वारा शासित नहीं हैं; तथा
- (ii) न्यायिक सेवा के अधिकारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान ढांचा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

3. इन नियमों के अनुसार पुनरीक्षित उपबन्ध उन सरकारी कर्मचारियों को लागू होंगे जो प्रभाव की तिथि। प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं/मृत्यु हो गई है:

परन्तु जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन या मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन का सरांशीकरण प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद आने वाले मामलों में पहले ही स्वीकृत हो गए हैं, उन्हें इन नियमों के निबन्धनों के अनुसार पुनरीक्षित किया जाए:

परन्तु यह और कि उन मामलों में जहां पेंशन पूर्व-पुनरीक्षित परिलाभों पर अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई है और यदि यह इन नियमों के अधीन हकदारी पेंशन से अधिक लाभकारी हो, तो पहले से ही स्वीकृत पेंशन हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 78 के परन्तुक को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों के अलाभ के लिए पुनरीक्षित नहीं की जाएगी।

पेंशन/पारिवारिक
पेंशन के लिए
परिलाभ।

4. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान से अन्यथा विभिन्न पेंशनरी लाभों को संगणित करने के प्रयोजन के लिए "परिलाभ" से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 8 के उपनियम (7) के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित वेतन।

मूल वेतन

5. पुनरीक्षित वेतन ढांचा में वेतन से अभिप्राय है, प्रथम जनवरी, 2016 से वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में प्राप्त किया गया वेतन किंतु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है।

मृत्यु एवं
सेवानिवृत्ति
उपदान के लिए
परिलाभ।

6. सभी प्रकार के उपदान सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, इन नियमों के नियम 4 के निबन्धनों में यथा परिभाषित परिलाभ सहित परिलाभों के रूप में समझे जाएंगे।

पेंशन।

7. दस वर्ष की अर्हित सेवा पूरी करने से पूर्व हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा किन्तु वह हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 32 तथा 35 के निबन्धनों में सेवा उपदान के लिए हकदार समझा जाएगा।

पेंशन की
संगणना हेतु
उपबन्ध।

8. (1) कोई सरकारी कर्मचारी जो बीस वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो वह हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 34 के उपबन्धों के अधीन पूर्ण पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) सभी ऐसे मामलों में जहाँ कोई सरकारी कर्मचारी, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 34 के अनुसार दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अधिवर्षिता पर पेंशन का हकदार हो गया है, वहां उसकी पेंशन उसे अनुज्ञेय पूर्ण पेंशन राशि के अनुपातिक आधार पर संगणित की जाएगी।

पेंशन की
न्यूनतम और
अधिकतम
सीमा।

9. (1) पेंशन की राशि, प्रथम जनवरी, 2016 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम 9,000/- रुपये और अधिकतम 2,24,100/- रुपये के उच्चतर वेतनमान का 50 प्रतिशत अर्थात् 1,12,050/- रुपये के अध्यक्षीन होगी।

(2) उपनियम (1) के उपबन्ध उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ किसी कर्मचारी का सेवाकाल उसकी सेवानिवृत्ति के समय पर 20 वर्ष से कम है। ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी की पेंशन, उसके सेवाकाल के दृष्टिगत हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार आनुपातिक रूप से संगणित की जाएगी।

अतिरिक्त
पेंशन/पारिवारिक
पेंशन

10. (1) वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मात्रा नीचे दी गई तालिका में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार संगणित की जाएगी:-

तालिका

क्रम संख्या	पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
1	2	3
1	80 वर्ष किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत।
2	85 वर्ष किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत।
3	90 वर्ष किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत।
4	95 वर्ष किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन /पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत।
5	100 वर्ष या अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन /पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत।

(2) प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) हरियाणा यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि तथा आयु पेन-1 तथा पेंशन भुगतान आदेश में स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है तथा पेंशन वितरण प्राधिकारी अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ज्योंही देय होती है, के भुगतान को सुकर बनाने के लिये पेंशन भुगतान आदेश करेगा। अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि पेंशन भुगतान आदेश में स्पष्ट रूप से दर्शाई जाए।

उदाहरण:- यदि जहां कोई पेंशनर 80 वर्ष से अधिक आयु का है तथा उसकी समेकित पेंशन 10,000/- रुपये प्रतिमास है, तो पेंशन (i) मूल पेंशन =10,000/- रुपये तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन =2,000/- रुपये प्रतिमास के रूप में दर्शाई जायेगी। 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन इस प्रकार दर्शाई जाएगी (i) मूल पेंशन =10,000/- रुपये तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन =3,000/- रुपये प्रतिमास।

(3) 80 वर्ष तथा अधिक की आयु पूरी करने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि मास के प्रथम दिन जिसमें उसकी जन्म की तिथि पड़ती है, से अनुज्ञेय होगी।

उदाहरण:- यदि कोई पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जुलाई, 2016 के मास में किसी तिथि को 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर वह प्रथम जुलाई, 2016 से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। जिन पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि पाँच जुलाई, 2016 है, तो वे भी 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रथम जुलाई, 2016 से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।

(4) महंगाई राहत, समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपलब्ध पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर भी अनज्ञेय होगी।

11. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा बीस लाख रुपये होगी। जब भी महंगाई भत्तों की वृद्धि मूल वेतन के 50% से अधिक हो जाती है, तो उपदान की सीमा में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी।

मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान।

12. (1) पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित वेतन ढांचे में मूल वेतन के 30 प्रतिशत की समरूप दर पर संगणित की जाएगी तथा न्यूनतम 9,000/- रुपये प्रति मास होगी तथा हरियाणा सरकार में प्रथम जनवरी, 2016 से उच्चतर वेतन 2,24,100/- रुपये का अधिकतम 30 प्रतिशत अर्थात् 67,230/- रुपये के अध्यधीन होगी।

पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1964।

(2) बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की राशि पुनरीक्षित वेतन ढांचा में मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी और न्यूनतम 9,000/- रुपये प्रति मास और हरियाणा सरकार में उच्चतर वेतनमान का अधिकतम 50 प्रतिशत के अध्यधीन होगी।

(3) पारिवारिक पेंशन, बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन और वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों की अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

13. इन नियमों के प्रयोजन के लिए, “पारिवारिक पेंशन” से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 8 के उपनियम (10) के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित पारिवारिक पेंशन।

पारिवारिक पेंशन की हकदारी।

14. संराशिकरण मूल्य, सीमा जिस तक पेंशन संराशित की जा सकती है अथवा अवधि जिस के बाद संराशित पेंशन बहाल की जानी है, से संबंधित उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

पेंशन का संराशिकरण।

15. इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार संगणित की गई समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, प्रथम जनवरी, 2016 से ‘मूल पेंशन’ अथवा ‘मूल पारिवारिक पेंशन’ जैसी भी स्थिति हो, समझी जायेगी। प्रथम जनवरी, 2016 से महंगाई राहत सहित प्राप्त की गई पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उसके बाद स्वीकृत महंगाई राहत प्रदान करने के लिए अर्हक होगी।

महंगाई राहत की हकदारी।

16. पेंशन संवितरण अधिकारी, भुगतानयोग्य पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों को संगणित करेगा और इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से अधिमन्यतः तीन मास के भीतर पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को बकायों का आवश्यक भुगतान करेगा।

उन कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकाया का भुगतान, जो प्रथम जनवरी, 2016 को सेवानिवृत्त हो गये हैं/मृत्यु हो गई है।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अधिक भुगतान की वसूली के लिए वचनबद्धता।

17. (1) यह असम्भाव्य नहीं है कि कुछ मामलों में देय बकाया का अधिक भुगतान गलती से संगणित किया जा सकता है जो बाद में वसूल किया जाना है। इसलिये पेंशन वितरण प्राधिकारियों को पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से बकाया निकालते समय यह स्पष्ट कर लेना चाहिये कि यदि कोई भिन्नता बाद में ध्यान में आती है, तो किये जा रहे भुगतान उन राशियों से समायोजन के अध्यक्षीन हैं जो उनको देय होगी। इस प्रयोजन के लिये, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों की निकासी के समय पर प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर से लिखित में इस आशय का एक वचन भी प्राप्त किया जाना चाहिये कि अधिक भुगतान जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गलत समेकन/बकायों की संगणना करने के परिणामस्वरूप किया गया पाया जा सकता है, तो उक्त राशि उस द्वारा सरकार को या तो भविष्य में भुगतान के समायोजन द्वारा या अन्यथा से वापिस किया जायेगा। वचन का नमूना प्रारूप संलग्न है जो अनुबन्ध-I पर है।

(2) पेंशन/पारिवारिक पेंशन का नियतन तथा बकायों का समायोजन भी कतिपय मामलों में परिशोधन तथा समायोजन के अध्यक्षीन होगा, जहां विशेष पेंशन या अनन्तिम पेंशन विधि न्यायालय के कुछ अन्तरिम आदेशों की सामर्थ्य में किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को प्रदान की गई है, मामले के अंतिम रूप से निर्णीत होने के बाद, विधि न्यायालय की टिप्पणी/निर्देश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकता है। इसलिये पेंशन वितरण प्राधिकारी, पेंशन/पारिवारिक पेंशन बकायों का वितरण करते समय सभी ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को यह भी स्पष्ट करेंगे कि भुगतान विधि न्यायालय के ऐसे अन्तिम निर्णय पर सरकार द्वारा लिये गये उचित निर्णय के अध्यक्षीन किये जा रहे हैं। वचन का नमूना प्रारूप भी संलग्न है जो अनुबन्ध-II पर है।

अध्यरोही प्रभाव।

18. इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय हरियाणा सिविल सेवा नियम या पंजाब वित्त नियम या इस संबंध में बनाए गये किन्हीं अन्य नियमों या जारी किये गये अनुदेशों के उपबन्ध इन नियमों या इन नियमों की निरन्तरता में जारी किये गये किन्हीं अन्य पश्चातवृत्ती अनुदेशों में उपबन्धित से अन्यथा, के सिवाय ऐसे मामलों को जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन को इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक वे इन नियमों से असंगत है।

निर्वचन।

19. यदि इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो यह निर्णय के लिये सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा।

अवशिष्ट उपबन्ध।

20. किसी सामान्य या विशेष परिस्थितियों की दशा में, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं या जिनके बारे में निश्चित असंगति ध्यान में आई हो, तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और सरकार ऐसी परिस्थितियों के अधीन अनुसरण की जाने वाली शर्तें विहित करेगी। इस नियम के अधीन सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी शर्तें इन नियमों का भाग समझी जायेंगी। आगे, यदि सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि कतिपय अतिरिक्त शर्तों को विहित करने की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी शर्तें विहित करेगी और सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी अतिरिक्त शर्तें इस नियम का भाग समझी जायेंगी।

ढील देने की शक्ति।

21. जहां सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि इन नियमों के सभी या किन्हीं उपबन्धों के संचालन में किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वह आदेश द्वारा ऐसी सीमा तक न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण मामले में संव्यवहार करने के लिए, जो वह उचित समझे, इन नियमों की अपेक्षाओं में ढील दे सकती है।

प्रदर्शन।

22. पेंशन वितरण प्राधिकारियों/खजाना अधिकारियों/सहायक खजाना अधिकारी इन नियमों को पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लाभ के लिये अपने सूचना पट्ट पर तत्काल प्रदर्शित करेंगे।

अनुबंध-I*[देखिए नियम 17 (1)]***वचनबद्धता**

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ कि कोई अधिक भुगतान जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गलत नियतन के परिणामस्वरूप किया गया पाया जा सकता है या बाद में ध्यान में आई भिन्नताओं के दृष्टिगत पता लगाया गया, कोई अधिक भुगतान मेरे द्वारा सरकार को या तो मुझको देय आगामी भुगतानों के समायोजन द्वारा या बकायों से वापस किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम

पता

अनुबंध-II*[देखिए नियम 17 (2)]***वचनबद्धता**

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ कि किसी विधि न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के आधार पर मुझे दी गई पेंशन में किसी परिशोधन या समायोजन के परिणाम के रूप में कोई अधिक राशि जो विधि न्यायालय के अंतिम निर्णय पर सरकार द्वारा लिए गए संबंधित उचित निर्णय के परिणाम के रूप में किया गया पाया जाएगा, तो वह मेरे द्वारा सरकार को या तो मुझको देय आगामी भुगतानों के समायोजन द्वारा या अन्यथा से वापस किया जाएगा। मैं आगे ऐसे विधि न्यायालय के यथास्थिति अंतिम निर्णय पर लिये गये सरकार के ऐसे संबंधित उचित निर्णय का पालन करने का वचन देता हूँ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम.....

पता

पी० राघवेन्द्र राव,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 3rd March, 2017

No. 2/23/2016-1Pension.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Services (Revised Pension) Part-II Rules, 2017. Short title and commencement.
 (2) They shall apply to all the employees who retire/die in harness on or after the 1st January, 2016 and who become eligible for pension/family pension under the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 and as applicable to the pensioners/family pensioners and whose pension/family pension is debitable to the Consolidated Fund of the State of Haryana.
2. These rules shall not apply to— Non-applicability of these rules.
 - (i) any category of employees whose services are not governed by the provisions of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 or any other provisions of service rules which are applicable in the case of pensioners; and
 - (ii) the officers of Judicial Services whose revised pay structure is yet to be finalized.
3. The revised provision as per these rules shall apply to Government employees who retire/die in harness on or after the 1st January, 2016 (separate rules are being issued in respect of retirees who retired/died before 1st January, 2016): Date of effect.
 Provided that where pension/family pension or death-cum-retirement gratuity/commutation of pension has already been sanctioned in cases occurring on or after the 1st January, 2016, the same be revised in terms of these rules:
 Provided further that in cases where pension has been finally sanctioned on pre revised emoluments and if the same happens to be more beneficial than the entitled pension under these rules, the pension already sanctioned shall not be revised to the disadvantage of the pensioner in view of proviso to rule 78 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.
4. The term “emoluments” for the purposes of calculating various pensionary benefits other than death-cum-retirement gratuity shall mean pay as defined in clause (b) of sub-rule (7) of rule 8 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016. Emoluments for Pension/Family Pension.
5. Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix with effect from the 1st January, 2016 but does not include any other type of pay like special pay etc. Basic Pay.
6. In the case of all kinds of gratuity, dearness allowance admissible on the date of retirement/death shall continue to be treated as emoluments along with the emolument as defined in terms of rule 4 of these rules. Emoluments for Death-cum-Retirement Gratuity.
7. A Government servant retiring in accordance with the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 before completing qualifying service of ten years shall not be entitled to pension but he shall continue to be entitled to service gratuity in terms of rules 32 and 35 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016. Pension.
8. (1) A Government servant, who retires after rendering the minimum qualifying service of 20 years, shall become entitled to full pension under the provisions of rule 34 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016. Provision for calculation of pension.
 (2) In all such cases where Government servant becomes entitled to pension on superannuation after completion of 10 years of qualifying service in accordance with rule 34 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules 2016, pension shall be calculated on proportion basis to the amount of full pension admissible to him.
9. (1) The amount of pension shall be subject to a minimum of ₹9000/- and the maximum ₹ 1,12,050/- i.e. 50% (fifty percent) of highest pay of ₹ 2,24,100/- in the Government of Haryana with effect from 1st January, 2016. Minimum and maximum ceiling of pension.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall not apply in those cases where the length of service of an employee at the time of his retirement is less than 20 years. The pension of these Government employees shall be calculated proportionately as per provisions specified in the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 keeping in view his length of service.

Additional
Pension/Family
Pension.

10. (1) The quantum of additional pension/family pension available to the old pensioners/family pensioners shall continue to be as specified in the table given below:—

Table

Serial Number	Age of pensioner/family pensioner	Additional quantum of pension/family pension
1	2	3
1.	From 80 years to less than 85 years	20% of revised basic pension/family pension
2.	From 85 years to less than 90 years	30% of revised basic pension/family pension
3.	From 90 years to less than 95 years	40% of revised basic pension/family pension
4.	From 95 years to less than 100 years	50% of revised basic pension/family pension
5.	From 100 years or more	100% of revised basic pension/family pension

(2) The Principal Accountant General (Accounts and Entitlement) Haryana shall ensure that the date of birth and the age of the pensioners/ family pensioners is invariably indicated in the PEN-I and the Pension Payment Order to facilitate payment of additional pension/family pension by the Pension Disbursing Authority as soon as it becomes due. The amount of additional pension/family pension shall be shown distinctly in the Pension Payment Order.

Illustration, In case where a pensioner is more than 80 years of age and his pension is ₹10,000 PM, the pension shall be shown as (i) Basic Pension= ₹10,000 and (ii) Additional Pension= ₹2,000 per month. The pension on his attaining the age of 85 will be shown as (i) Basic Pension= ₹10,000 and (ii) Additional Pension= ₹3,000 per month.

(3) The Additional quantum of pension/family pension on attaining the age of 80 years and above shall be admissible from the first day of the month in which his date of birth falls. For example, if a pensioner/family pensioner completes the age of 80 years in the month of July, 2016, he shall be entitled to additional pension/family pension with effect from the 1st July, 2016. Those pensioners/family pensioners whose date of birth is 5th July, shall also be entitled to additional pension/family pension with effect from 1st July, 2016 on attaining the age of 80 years and above.

(4) Dearness relief shall also be admissible on the additional quantum of pension/family pension available in accordance with the orders issued from time to time.

Death-cum-
Retirement
Gratuity.

11. The maximum limit of death-cum-retirement gratuity shall be ₹20.00 Lakh (twenty lakh). The ceiling on gratuity shall increase by 25% (twenty five percent) whenever the dearness allowance rises by 50% (fifty percent) of the basic pay.

Family Pension
Scheme, 1964.

12. (1) Family pension shall be calculated at a uniform rate of 30% (thirty percent) of basic pay in the revised pay structure and shall be subject to a minimum of ₹9,000/- per month and maximum of ₹67,230/- i.e., 30% of the highest pay of ₹2,24,100/- in the Government of Haryana with effect from the 1st January, 2016.

(2) The amount of enhanced family pension shall be 50% (fifty percent) of basic pay in the revised pay structure and shall be subject to a minimum of ₹9,000/- per month and maximum of 50% of the highest pay in the Government of Haryana.

(3) There shall be no other change in the provisions regulating family pension, enhanced family pension and additional family pension to old family pensioners.

Entitlement of
family pension.

13. For the purpose of these rules, “family pension” means, the family pension as defined in sub-clause (b) of clause (10) of rule 8 of the Haryana Civil Service (Pension) Rules, 2016.

- 14.** There shall be no change in the provisions relating to commutation values, the limit upto which the pension may be commuted or the period after which the commuted pension is to be restored. Commutation of Pension.
- 15.** The consolidated pension/family pension as worked out in accordance with the provisions of these rules shall be treated as "Basic Pension" or "Basic Family Pension", as the case may be, with effect from 1st January, 2016. The revised pension/family pension arrived includes dearness relief from the 1st January, 2016 and shall qualify for grant of dearness relief sanctioned thereafter. Admissibility of dearness relief.
- 16.** The Pension Disbursing Authorities shall calculate the arrears of revised pension/family pension payable and make necessary payment of arrears to the pensioners/family pensioners preferably within 3 months from the date of notification of these rules. Payment of arrears of pension/family pension to those employees who retired/died after 1st January, 2016.
- 17.** (1) It is not unlikely that the arrears due in some cases may be calculated incorrectly leading to over payment that might have to be recovered subsequently even after this exercise. The Pension Disbursing Authorities shall, therefore, make it clear to the pensioners/family pensioners while drawing arrears of pension that the payments are being made subject to adjustments from amounts that may be due to them, if any, discrepancy is noticed later. For this purpose an undertaking shall be obtained in writing from every pensioner/family pensioner at the time of revision of pension/family pension to the effect that excess payment that may be found to have been made as a result of incorrect consolidation of pension/calculation of arrears shall be refunded by him to the Government either by adjustment against future payment or otherwise. A specimen form of undertaking is enclosed as Annexure-I. Undertaking for recovery of over payment of pension/family pension and gratuity.
- (2) The fixation of pension/family pension and adjustment of arrears shall also be subject to rectification and adjustments in certain cases where a particular pre-revised scale or provisional pension has been granted to a Government servant/pensioner at the strength of some interim orders of the court of law, after the final disposal of the case suitable appropriate decision may be taken by the Government keeping in view the observation/instructions of the Court of law. The Pension Disbursing Authorities should, therefore, also make it clear to all such concerned employees/pensioners while disbursing the arrears/pension that payments are being made subject to appropriate decision taken by the Government on such final decision of the Court of law. A specimen form of undertaking is also enclosed as Annexure - II.
- 18.** The provisions of Haryana Civil Service Rules or Punjab Financial Rules or any other rules or instructions made or issued in this regard shall not, save as otherwise provided in these rules or any other subsequent instructions issued in continuation to these rules, apply to cases where pension/family pension and death-cum-retirement gratuity is regulated under these rules to the extent they are inconsistent with the provisions of these rules. The provisions of CSR Vol. II and other rules which are not specifically modified by these rules will remain unchanged. Overriding effect.
- 19.** If any question arises relating to the interpretation of the provisions of these rules, it shall be referred to the Government of Haryana in Finance Department for decision. Interpretation.
- 20.** In the event of any general or special circumstance which is not covered under these rules or about which certain inconsistencies are noticed, the matter shall be referred to the Government and the Government shall prescribe the conditions to be followed under such circumstances. Such conditions as prescribed by the Government under this rule shall be deemed to be part of these rules. Further, if the Government is satisfied that there is a requirement to prescribe certain additional conditions, the Government may prescribe such conditions and such additional conditions as prescribed by the Government under this rule, shall be deemed to be the part of these rules. Residuary provisions.
- 21.** Where the Government is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may, by order, dispense with or relax the requirements of these rules to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. Power to relax.
- 22.** The Pension Disbursing Authorities/Treasury Officers/Assistant Treasury Officers shall promptly display these rules on their notice board for the benefit of pensioners/family pensioners. Display.

ANNEXURE I*[See rule 17 (1)]***UNDERTAKING**

I hereby undertake that in case excess payment is found to have been made as a result of incorrect fixation of pension/family pension or any excess payment detected in the light of discrepancies noticed subsequently shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Date:

Place:

Signature_____

Name _____

Address _____

ANNEXURE II*[See rule 17 (2)]***UNDERTAKING**

I hereby undertake that as a result of any rectification or adjustment in the pension granted to me on the basis of any interim order by any Court of law, any excess amount which is found to have been made as a result of relevant appropriate decision taken by the Government on the final decision of the Court of law, shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise. I further undertake to abide by such relevant appropriate decision of the Government taken on the final decision of such Court of law as the case may be.

Date:

Place:

Signature_____

Name _____

Address _____

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.